



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 1981/ज्येष्ठ 19, 1903

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 1981/JYAISTHA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रहा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 47-ई टी सी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 9 जून, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय: 1981-82 के दौरान भारतीय बकरों के मांस के निर्यात से
संबंधित नीति।

सं० सं० 1/28/81-ई० 1.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण)
मंत्रालय आदेश सं० ई (सी) ओ, 1977/एएम(210), दिनांक 9 जून
1981 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसकी शर्तों के अनुसार बकरों
के मांस के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

2. सांख्यिक आश्वासन पर जारी किए जाने वाले सीमित उच्चतम
सीमा के भीतर भारतीय बकरों के मांस के निर्यात की अनुमति देने के
लिए निम्नलिखित किया गया है जो न्यूनतम प्रति किलो ग्राम 16 रुपये जहाज
पर निःशुल्क मूल्य का निर्यात कीमत के अधीन है। उच्चतम सीमा ताजा
मांस और जीवंत पशु धन निर्यातक मधु, बम्बई और साथ ही साथ गुजरात
राज्य निर्यात निगम लि० अहमदाबाद, के पास निपटान की लिए रखी
गई है। कोटे का नियन्त्रण जहाजरानी बिल/वायुयान द्वारा पृष्ठांकन करके किया
जाएगा। यह पृष्ठांकन पथ्य वस्तु की शीघ्र मंडने की प्रवृत्ति का ध्यान में
रखते हुए अधिकतम 72 घंटे की अवधि के लिए वैध होगा। उपर्युक्त
निर्यातों का देशी मंडियों में माल की उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित
किया जाएगा या निम्नलिखित पैर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

3. उपर्युक्त बातों का ध्यान में रखकर निम्नलिखित प्रविष्टि अप्रैल
1981-मार्च 1982 की निर्यात नीति के नीति विवरण की क्रम सं०
6(ख) के बाद पृष्ठ सं० 11 पर निम्न प्रकार से जोड़ी जाएगी:—

1	2	3
6(ग)	भारतीय बकरों के मांस जिनमें हृदय, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, किडनी और अन्य भाग शामिल हैं।	भारतीय बकरों के मांस के निर्यात की अनुमति जहाजरानी बिल/वायुयान बिल प्रस्तुत करने पर सांख्यिक आधार पर रिलोज का जाने वाला सामित उच्चतम सीमा के भीतर 16 रुपये प्रति कि०ग्रा० जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अधिकतम निर्यात कीमत के अधीन दी जाएगी जो निम्न- लिखित शर्तों के अधीन है:—
		(1) निर्यात एकदम बिजरी के आधार पर होगा और किसी प्रकार के परेषण निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
		(2) कोटे का नियन्त्रण जहाजरानी बिल/वायुयान बिल पर पृष्ठां- कन करके किया जाएगा जो अधिकतम 72 घंटे की अवधि के लिए वैध होगा।

1	2	3	1	2	3
(3)	उच्चतम सीमा तक ताजा मांस और जीवित पशु निर्यात संघ, बंबई और गुजरात राज्य निर्यात निगम लि०, ब्रह्मबाबाद के पास सिपटान के लिए रखा जाएगा। कांटे का नियमन करने के लिए प्रतिकरणों द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन का अनुसरण करना होगा :		(4)	नियत एजेंसियों को पूर्व के महीनों में किए गए निर्यातों की सूचना वाणिज्य मंत्रालय को अगले महीने की 7 तारीख तक देंगे।	
(क)	नियमन एजेंसियों को इस बात का सुनिश्चय करने के बाद कि जीवित बकरों को मारने के लिए स्थानीय मंडी में खरीद हम बात का सुनिश्चय करने के बाद की जाती है कि घरेलू बाजारों में रोज-रोज की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। यदि किसी खास दिन को इस जरूरत से काम कुछ आसानी होती है तो निर्यात के लिए किसी प्रकार की खरीद नहीं की जाएगी।		(4)	सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति ताजा मांस और जीवित पशु धन निर्यातक संघ द्वारा नियत किए गए कांटे के आधार पर सीधे ही किया जाएगा। गुजरात राज्य निर्यात निगम लि० के मामले में निर्यात उनके खाते पर ही किए जाएंगे।	
(ख)	यदि उपर्युक्त (क) की शर्तें पूरी की जाती हैं तो निर्यातक मारने के लिए बकरों की खरीद के लिए बाजार में जब आएंगे जब घरेलू जरूरतों के लिए खरीद कर ली जाती है। इसी आधार पर वे कल्प गृह का उपयोग तब करेंगे जबकि घरेलू उपयोग के लिए बकरों को मारने का काम पूरा हो जाता है।				
(ग)	संघ द्वारा एक निर्यातक को इसका नियमन पहले आए तो पहले पाए के आधार पर करना चाहिए लेकिन निर्यात नीति 1981-82 के पैरा 14 की व्यवस्थाएं इस मामले में लागू नहीं होगी।				
(घ)	पशु वस्तु की गीश्र मंडने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और हम बात को भी ध्यान में रखते हुए कि मासिक उच्चतम सीमा को पूरा किया जाता है, एक नियमित को कांटे के नियमन की वैध श्रवधि 72 घंटे ही होगी।				

1	2	3	1	2	3
		(ii) The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/Airway Bills valid for a maximum period of 72 hours.			(c) Allocation to individual exporters by the Association should be made on first-come, first-served basis. However, provisions of Para 14 of Export Policy 1981-82 will not apply in this case.
		(iii) The ceiling will be placed at the disposal of Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association at Bombay and the Gujarat State Export Corporation Ltd., Ahmedabad.			(d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceilings will have to be met, the validity of quota allocation to individual exporters will be 72 hours only.
		The following guidelines will be followed by the agencies regulating the quota.			
		(a) The designated agencies should ensure that exporters purchase live goat for slaughter from the local mandis only after the daily requirements in the domestic market are met. If the total arrival on any particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made.			(e) The designated Agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of exports made during the preceding month.
		(b) In case the condition at (a) above is met, exporters will enter the market for purchase of goat for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. Similarly they will use the Slaughter House only after slaughtering for domestic consumption has been done.			(iv) The export will be allowed by the customs Authorities directly on the basis of quota allocation made by Fresh Meat and Live Stocks Exporters' Association. In the case of the Gujarat State Export Corporation Ltd., exports will be done on their own account.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports

